

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 10/2021

जगन पुत्र चरन सिंह जाति गुर्जर निवासी खेरीडांग तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोजेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 18.02.2021 तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 02/2021 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम जगन अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :- 1. श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय


दिनांक : 28.07.2021

अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रैस्पोजेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 18.02.2021 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुये आराजी खसरा नम्बर 1722 रकवा 5.25, 1734 रकवा 1.30 हैक्ट0 वाके ग्राम खेरीडांग की सिवायचक भूमि से बेदखल कर पैनल्टी एवं 90 दिवस की सिविल कारावास की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

An
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई।
मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काविल खारिजी के है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि खण्ड पर अपीलांट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है, इस बाबत पटवारी हल्का ने अपीलांट को विवादित भूमिखण्ड को नापकर कभी भी अबगत नहीं कराया है। अपीलान्ट को नोटिस मिलने पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में यह अंडरटेकिंग दे दी थी कि यदि अपीलांट का कब्जा पाया जाता है, तो उसे चिन्हित कर दें, वह मौके पर से कब्जा हटाने को तैयार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने 90 दिन के सिविल कारावास की सजा देने में कानूनी भूल की है। पत्रावली पर इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं है, जिससे यह सावित होता हो कि अपीलांट को पहले वास्तव में कभी मौके से वेदखल कर दिया गया हो व बाद में पुनः सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया हो, उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी अवैधानिक रूप से माना गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पश्चातवर्ती कब्जा मानकर सजा देने में कानूनी भूल की है। अपीलांट को साक्ष्य पेश करने तक का कोई मौका नहीं दिया गया है, पटवारी से जिरह करने का मौका भी नहीं दिया गया है, पूर्व में पारित तथाकथित आदेश की कापी पेश नहीं की है, तहसीलदार ने मौके पर जाकर स्वयं ने अतिक्रमण की पुष्टि नहीं की है, मात्र पटवारी के बयान पर विस्वास करके अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजा कर दी है, आदेश अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 18.02.2021 को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी पुष्टि तहत अदालत में मुकदमा नम्बर 146/2020 निर्णय दिनांक 11.09.2020 से होती है। अपीलान्त को पूर्व में भी वेदखल किया गया था इस तरह यह साबित हो जाता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर 1722, रकवा 5.25 है० में से 0.16 है० एवं खसरा नम्बर 1734 रकवा 1.30 में से 0.24 है० ग्राम खेरीडांग किस्म सिवायचक में सरसो, गेहूँ (रवी) काशत किये जाने पर अपीलान्त को बेदखल एवं पैनल्टी तथा 90 दिवस की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। चूंकि विवादित आराजी की किस्म सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्त विवादित आराजी पर अतिक्रमी है अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त के खिलाफ पूर्व में दायर मुकदमा संख्या 146/2020 से पुष्टि हो जाती है जिसका निस्तारण दिनांक 11.09.2020 को किया जाकर अपीलान्त को मौके से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। वकील अपीलान्त




अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों को आधारहीन होने की पुष्टि करते हो तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को मूल पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)